IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखण्ड के उजड़ते गावों का पर्यटन पर प्रभाव नैनीताल जिलें के रामगढ़ स्थित रिया गांव (बहराकोट) का एक अध्ययन।

Dr Beena Joshi
Assistant professor political science
Government girls pg college haldwani nainital uttrakhand

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड राज्य की अवधारणा के पीछे यहां की दुर्गम परिस्थितियां व संवेदनशील हिमालय की चिन्ता छिपी थी। पिछले 15 वर्षों में 3600 गाँव खाली हो चुके हैं कुछ गाँव बंजर होना शुरू हो गए हैं कुछ ऐसे हैं जहां गिने चुने बुजुर्ग ही रहते हैं भुतवा होते गाँव सरकार को डरा नहीं पा रहे हैं पहाड़ों पर डॉक्टर व अध्यापक जाने को तैयार नहीं हैं। 1800 विद्यालय बन्द होने के कगार पर हैं। कृषि की स्थिति बदहाल है 70,000 हेक्टेयर खेतीहर जमीन कम हो गई है। बेरोजगारी ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये है, 4 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से मात्र 31,145 को ही रोजगार मिल पाया है। इन तमाम दुश्वारियों की वजह से लोग राज्य से पलायन करने लगे हैं। अल्मोड़ा व पौड़ी जैसे जिले भी जल्दी ही बंजर होने के कगार पर हैं उत्तराखण्ड के लगभग 35–40 प्रतिशत से ज्यादा की आवादी राज्य छोड़ चुकी है। सच्चाई यह है कि शासन प्रशासन देश को आकड़ों में उलझाये रखी है। उत्तराखण्ड बनने के बाद 32 लाख लोगों ने पहाड़ छोड़ दिया है अब वक्त आ गया है इसे रोका जाए गाँव की सुद ली जाय अन्यथा समस्या से निपटना नामुंकिन हो जायेगा।

हिमालय की मिट्टी और जल पूरे देश के नाम आता है हिमालय ऑक्सीजन का भण्डार है तथा जलवायु को नियंत्रित करता है। उपभोगतावादी अविवेकपूर्ण विकासवादी दृष्टि कभी हिमालय में टिकाऊ विकास नहीं कर सकी पहाड़ के गाँव शहर की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं जंगल, पानी व मिट्टी होने के बाद पहाड़ को विकास से वंचित रखा जाना असमानता है। शहर का समाज सब कुछ भोगे और पहाड़ के गाँव इससे वंचित रहे। 'असुविधा ही समस्या की जड़ है' शहर के पास सब कुछ है तथा पहाड़ का गाँव उससे वंचित है तो सब कुछ चरमरा जाना तय है। पहाड़ से मैदान की तरफ ही पलायन नहीं हो रहा है वरन् पहाड़ के गाँवों पहाड़ के शहर की तरफ भी भ्पपलायन हो रहा है।

समस्या का कारण– (पर्यटन व राजनीतिक विकास की लौ से दूर है गाँव) पिछले 18 वर्षों में नौ मुख्यमंत्री दिये हैं राजनेताओं की चिन्ता राज्य की खुशहाली नहीं वरन् कुर्सी कायम रखने की है। जैसे– असुविधा, भूगोल, चढ़ाई, सूनसान रास्ते, यातायात के साधनों का अभाव, सर पर सामान ढोना, अशिक्षा, तकनीक का अभाव, निम्न रहन–सहन, प्रौद्योगिकी व उद्यम का अभाव महिलाओं की शहर की चकाचौध भरी जिन्दगी की ओर रूझान, काम न करने की परम्परा का उदय, वैज्ञानिक वातावरण व तकनीक का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल न होना। 2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ही राजनीतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धीरे विजली चलित उद्योगों का विकास न होना, संचार व इन्टरनेट से गांवों को न जोड़ना, कृषि कार्य का परम्परागत तरीका, विशिष्ठ (Specialized Agriculture) कृषि परम्परा का उदय न होना, पहाड़ के प्रति पहाड़वासियों द्वारा ही न रहने की मानसिकता का उदय होना, डेनमार्क की तर्ज पर 'डेरी उद्योग' का सही विकास न होना।

राशन की सरकारी दुकानों से बाहर आकर सरकार नये उद्यम स्थापित नहीं कर पा रही है। मेहनत करने के बजाय इन दुकानों के सस्ते राशन का ही इन्तजार पहाड़ी गाँव के लोगों को रहता है। परिणाम स्वरूप पुराना तरीका जारी रहता है तथा अकर्मण्यता का उदय हो रहा है।

पहाड की वस्तु की पहाड में कीमत क्यों नही होती–शहर में आते ही उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। विपणन व्यवस्था की सही नीति नही होने के कारण सेब,आडू,पुलम, खुमानी, गढमेहल, को मार्केट नही मिलती तथा वह खेतों में ही सड़ा रहता है जबकि भारत में सूखी खुमानी विदेशों से 100रू0 प्रति पैकट की दर से मंगायी जाती है जबकि सरकार को विदेशों से फल की बजाय ड्राई फ्रुट की तकनीक लाकर सम्बन्धित उद्योग पहाड के गांव में ही लगाया जाना चाहिये था। पहाड के गांव को उद्यमी सरकार की जरूरत है जो अभी तक नही मिल पायी। गांव के पास से गुजरती सडक का फायदा तो है लेकिन आर्थिक फायदा नही जब तक कि गांव के कच्चे रास्तों को भी सड़क में तबदील न कर दिया जाये। सरकार को परिवहन के साधन भी पहाड के हिसाब से हल्के बनाये जाने चाहिये जो गांव खतरे की जगह स्थित नही है उनका सर्वे कराकर घरों को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप आर्कषक बनाकर स्टे होम के रूप में पर्यटकों को आर्कषित किया जा सकता है। दो पेड़ देने की नीति छोड़कर गांव के युवकों का स्क्लि डेवलपमेंट कर बागवानी की ट्रेनिंग दी जाये ताकि नर्सरी तैयार कर सैकडो पेड़ लगे तथा कूमर (कांटा) वाली घास से निजात मिल सके। चीड़ के पेड़ से ही अनेक उद्योग वहा पर स्थापित किये जा सकते है जैसे – माचिस, लीसे से वार्निस, ज्वैलरी, जंकरोधक कोटिंग, कोल ब्लॉक, आइनमेंट जबकि लीसा सीधे मैदानों को चला जाता है।

स्वयं गाँववासी भी जिम्मेदार– उद्यम का अभाव – Political Development व Awareness अभावों के कारण सब कुछ होने के बावजूद (जैसे प्रकृतिक संसाधन, हरीशब्जी, फल, दालें, दही, मठ्ठा स्वच्छ वायु, शान्त वातावरण) वह सरकार की पहाड़ के हिसाब से ठोस नीति नही बनाये जाने के कारण तथा गाँव वालों द्वारा वोट का सही इस्तेमाल वह इन चीजों की वैल्यू नहीं पहचानता है परिणाम स्वरूप वह आर्थिक लाभ नहीं उठा पाता है। जैसे– गाँव के हर परिवार औंसतन् 10 किग्रा गौहत पैदा कर लेता है इसमें से 2 किग्रा बीज के लिए तथा खाने के लिए रखता है। 8 किग्रा, बिचौलियों को बेच देता है जो इसकी वैल्यू से वाकिफ होता है शहर से आकर ले जाता है। गाँव के परिवार को वह 30 रूपये किग्रा के हिसाब से देता है शहर जाकर 135 रूपया किग्रा बेचता है। अगर गाँव के लोग ग्रुप बनाकर पैकिटिंग की मशीन का इस्तेमाल कर ऑनलाईन बेच देता है तो उसे पर किलो 100 रूपया मिलता तथा 35 रूपया पैकिटिंग

बगैराह में खर्च होता। गाँव में ही अनेकों रोजगार इस तरह से मिलता तथा पलायन रूकता। गाँव के लोग कुपोषण के शिकार हैं हरी शब्जी खाते ही नहीं हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना का भी अभाव है। सुस्त जिन्दगी जीते हैं, और लाभदायक कृषि उत्पादों का उत्पादन करते हैं।

सरकार समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार—(गाँव के प्रति सरकार की मनोवृत्ति) सरकार ठोस नीति के अभाव के कारण गाँववासियों को सस्ता अनाज व मिट्टी तेल देकर गरीब बनाती गयी तथा वे कभी 'उद्यमी' नहीं बन पाये परिणाम स्वरूप वह मैदानी लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से अछूते गाँव उदासीन, अकेलेपन के शिकार हैं। राज्य सरकार 4—5 शहरों को तो चमका रही है गाँवों को छोड़ दिया है। यही करना है कि उत्तराखण्ड के गाँव हिमांचल के गाँवों की तरह विकास नहीं कर पा रही है। 'राजधानी उपयुक्त जगह पर नहीं है' देहरादून की अधिकांश जनसंख्या उत्तराखण्ड की नहीं है उनका पहाड़ के गाँव से भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक संबंध नहीं है। हिमांचल की तरह वाई एस0 पर मार जैसे दूर दृष्टा मुख्यमंत्री (1967—77) तक, ने अच्छे स्कूल व अस्पताल बनाने के लिए नौकरशाही को प्रेरित किया। 'मानव विकास' के मामले ने पहाड़ी हिमांचल राज्य का रिकार्ड केरल जैसा है। जबकि उत्तराखण्ड के 7 मुख्यमंत्रियों में से कुछ नाकाबिल तो कुछ औसत दर्जे के रहे हैं। भूमाफियों को सक्रियता बढ़ी है जिनकी विधायकों व मंत्रियों से सहभागिता रही है। हिमांचल का नौकरशाही' अपने काम कर अधिक केन्द्रित व मेहनती है जबकि उत्तरांचल की उदासीन व सुस्त। उत्तराखण्ड के राजनीतिक नेतृत्व ने 'नौकरशाही को नकारात्मक रूप से बढ़ावा दिया है' चन्द मैदानी भागों में सिमटी सरकार बंजर होते गाँवों के लिए कोई पर्यटन नीति नहीं बना रही है।

परिकल्पना
(पर्यटन की चुनौती रिया गांव के संदर्भ में)

नैनीताल जिले के अन्तर्गत भवाली से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव है जो प्राकृतिक संसाधनों व भूमिगत जलस्त्रोत, दोनों तरफ से दो छोटी गधेरों व सेब के बगीचों से सम्पन्न है फिर भी गाँव आर्थिक विकास को तरस रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वर्फ से भरी चौटियों से घिरा होने के बावजूद गाँव 40 साल के अन्दर इतनी तेजी से खाली हुआ है कि 10 साल बाद केवल 1 परिवार ही गाँव में रहेंगे। अकेलापन, उदासीनता, सुविधाओं का अभाव तेजी से पलायित गाँव भविष्य की भयावह तस्वीर पेश करता है।

40 वर्ष पूर्व गाँव के परिवारों की स्थिति

वर्ष	परिवार	जनसंख्या	व्यवसाय	नौकरी
1918	10	57	कृषि, दुग्ध उत्पादन मजदूरी व बागवानी	05

1918 में बागवनी व कृषि से इतना होता था कि परिवार के पास भरण—पोषण मेहनत से हो जाता है आज स्थिति भयावह। फल—खुबानी, काफल, पुलम, अलपोखर, चुंगारू, अखरोट, माल्टा, नारंगी, नाशपाती, गड़मेहल से पेड़ तदे रहते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि चखने को भी नहीं मिलते है। रंगविरंगे फूल, मधुमक्खी के बख्से भी रखे जाते थे लेकिन आज बख्सा भी नहीं है।

वर्ष	परिवार	जनसंख्या	व्यवसाय	नौकरी
1918	01	02	कृषि, पशुपालन, मजदूरी, बागवानी,नौकरी	सरकारी नौकरी, 01 व्यक्ति

पलायन का गाँव पर प्रभाव– गाँव के दिल्ली के होटलों में काम करने वाले गाँव की सड़क किनारे की पानी वाली जमीन को खुद खेत में मेहनत करने के बजाय भूमाफिओं को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो सरकारी ऑफिस या छोटे उद्योग खोलकर गाँव वालों को रोजगार दे सकती थी पर ऐसा हुआ नहीं।
गाँव के राजनीतिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व – ग्राम प्रधान के पद पर 35 साल तक एक ही परिवार का बना रहना तथा उस परिवार का गाँव छोड़कर शहर से गाँव देखना, वंशवादी व परिवारवादी राजनीति का उदाहरण है। गाँव को इसे तोड़कर निर्णय–निर्माण (Decision-Making) में जुड़कर सरकार पर दबाव बनाकर (Expansion of Public participation) का विस्तार कराया जाना चाहिए। कुशल नेतृत्व का अभाव भी गाँव में है। 2 प्रतिशत छोड़कर वोट की शक्ति से अनभिज्ञ है आडू नाशपाती, पुलम, गढ़मेहल खेतों में सड़ता है अगर सरकार इसके Packeging की व्यवस्था कर ट्रासपोर्ट की सुविधा देकर छोटी गाड़ी जाने लायक सीमेन्ट की पक्की सड़क बनाकर उचित मूल्य दिलाती तो विचौलिया ही 10 गुना ज्यादा रेट प्राप्त करने में सफल नहीं होता। अच्छा मूल्य प्राप्त करने पर गाँव के लाये ढावों में मजदूरी करने के लिए पलायित नहीं होते।
रामगढ़ गाँव के पलायन की तुलना स्विस गाँव Apples से पहाड़ से पलायन को रोकना है तो राजनीतिक व आर्थिक विकास के स्विस मॉडल को अपनाना होगा।

वर्ष	**राज्य**	**जिला**	**गाँव का नाम**	**परिवार**		**पलायित परिवार**	**भविष्य में पलायन**	**व्यवसाय**	**राजनीतिक हल**
				जन	**परिवार**				
2018	उत्तराखण्ड	नैनीताल	रिया	57	10	09	01	कृषि पशुपालन मजदूरी, बागवानी	0

स्विस गाँव

वर्ष	देश	केन्टन	जिला	गांव का नाम	परिवार	जनसंख्या	राजनीतिक दल	व्यवसाय	पलायन
2018	स्विटजरलैण्ड	टंनक	Morgas	Apples	223	1306	Green party, LPS party	Sports center, Nursing home riding school	गांव से बाहर नहीं वरन गांव की ओर

स्विस Apples गाँव का भूगोल रिया गाँव से भी मुश्किल भरा है। स्विटजरलैण्ड 07 पहाड़ियों से घिरा देश है यही कारण है कि गैरसैण को मीनी स्विटजरलैण्ड कहा जाता है। Alps व Jura की उच्च पर्वत श्रेणियों ने इसके 22 प्रतिशत भाग को अनुर्वर बना दिया है। आधुनिक तकनीक व राजनीतिक विकास के कारण इस देश के पर्वतीय गाँव काफी विकसित हैं। देश के पास खुद का लोहा, कोयला नहीं होने के बावजूद यहां के कुटीर उद्योग विकसित है।

यहां के गाँव से पलायन नहीं हुआ है वरन् बाहर से लोग पलायित हुए है। पर्वतीय नदियों व झीलों के बाहुल्य से यातायात व संचार में काफी कठिनाई आती है इसके बावजूद भी प्राकृतिक उद्योग की काफी गुंजाइस बचती है Wood Carving, Lace-Making Embroidery, कपड़े, दुग्ध पदार्थ, शूक्ष्म यंत्रों को आधुनिक तकनीक से बनाने की काफी सम्भावनाएं बचती हैं। सरकार ठोस नीति अपनाये तो इस तरह के उद्यम को गांव में ही स्थापित कर सकती है। स्विस गाँव साधनों की दृष्टि से काफी गरीब है लेकिन निवासी महान व समृद्ध है। स्विस गाँव के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रिया गाँव को उठाने की मनोवृत्ति सरकार के पास नहीं है। दुग्ध व्यवसाय बघाड़ गाँव का मुख्य व्यवसाय है लेकिन आय काफी कम होती है। 01– से 04 लीटर तक दुग्ध वाली गाय पाली जाती है। गाँव के लोग यथा स्थिति से आगे नहीं बड़ पा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को गाँवों द्वारा न समझना, विदोहन की उत्तम तकनीक का अभाव, फल

वागवानी का परम्परागत तरीका, शिक्षण व स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव, बजार की सही जानकारी का अभाव की पलायन को प्रात्साहित कर रहे हैं।

पर्वतीय काम को मैदानी व तराई भाग से अलगकर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रयोग की कम जनसंख्या के कारण संभव है। Apples नामक गाँव जो Jura Mountain पर स्थित हैं 223 परिवार अपना प्रशासन खुद करते हैं। कलपुर्जे की छोटी–छोटी फैक्ट्रीयां हैं रोजगार आसानी से मिल जाता है गाँव को सीधे पर्यटन से जोड़ा गया है। गाँव के लोग एल0पी0एस0 व ग्रीन पार्टी से जुड़े हैं। Apples गाँव में प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी दृढ़ इच्छा शक्ति व कल्पना शक्ति का प्रयोग कर आधुनिक अर्थ व्यवस्था का निर्माण किया है, गाँव के रहन–सहन का स्तर सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर विद्युत शक्ति व मानव शक्ति का उपयोग अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है खेती योग्य भूमि का चप्पा–चप्पा इस्तेमाल होता है। जबकि बघांण गाँव के बड़े–बड़े खेत बंजर पड़े हैं।

घरेलू बाजार की लघुता, कच्ची सामग्री के अभाव, चारों ओर से भूबद्ध स्थिति तथा राष्ट्रीय चरित्र का ही परिणाम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यहां के आर्थिक विकास, रोजगार, व उत्पादन की स्थिति में लगातार उन्नति हुई है। रिया गाँव का आर्थिक व राजनीतिक विकास कैसे हो? सर्वप्रथम सरकार को विज्ञापन के जरिए गाँव की मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाना होगा। शहर के लोगों के बीच जाकर गाँव की खूबियों को समझाना होगा ताकि लोग मानसिक रूप से गाँव की ताजी हवा की ओर जाने को कदम बढ़ायें। इसके पश्चात् गाँव को स्टडी करवाकर कि प्राकृतिक संसाधन क्या–क्या है और उनको कैसे संवर्धित किया जाय। इन्टरनेट के प्रशिक्षण की सुविधा गाँव में ही कार्यालय खोलकर उपलब्ध करायी जाय।
बास की खेती, सहतूत की बागवानी, (रेशम उत्पादन), मौन पालन, गुलाब की खेती, लेमन ग्रास उत्पादन (कीट नाशक) भांग की खेती, तुलसी की खेती, गाय पालन (गोमूत्र, गोबर) की व्यवस्था से Modern Techneque कराई जाये। प्रकृति ने, तिमूर, सम्यो, चीड़ के पत्ते, बुरांश, किल्मोड़ी की जड़, मिनरल वाटर, आँवला, स्यूता (चीड़ का फल का दाना) दिया है गधेरे के किनारे – किनारे अखरोट की पौध लगवायी जाय बहुत सारे गाँवों को जोड़कर उत्पादन के आधार पर उत्पाद के संवर्धन, पैकिटिंग, विपणन की व्यवस्था सरकार नीति बनवाकर करें, पानी की तकनीक से खेतों को उपलब्ध कराया जाय आयुर्वेदिक प्लान्ट भी सरकार लगा सकती है। जो उद्योग लग सकते हैं गाँवों का ग्रुप बनाकर 1– दुग्ध डेरी 2– उपलपैकिटिंग (ऑनलाईन मांग) 3– खाद पैकिटिंग, 4– गोमूत्र–शोध 5– अखरोट पैंकिंग 6– तुलसी पत्ते का, पुदीने का, गुलाब के फूल का अर्क 7– खुमानी, पुलम, चुंगारू का ड्राइफ्रूट्स तैयार करना 8– किमोड़ी की जड़ से मधुमेह की दवा व रंग बनवाना 9– बुरांश के फूल से स्क्वेस 10– भांग के पेड़ के रेशे से कैरी बैग 11– शहद पैकिंग 12– बॉस से बुलेट प्रुफ 13– लेमन ग्रास से मच्छर रोधी दवा 14– आटा पीसने के पुराने घराट को जीवित करना।

गाय के गोबर के उपल की विदेशों में भारी मांग है उपल बनाकर पैंकिंग कर वासमती चावल की तरह ऑनलाईन बिक्री करवाकर भारी अर्जन किया जा सकता है। जब गाँव हरा–भरा, फल–फूलों से लदा होगा तो स्वाभाविक है कि वह भी पर्यटन की ओर आकर्षित होगा। गाँव के निवासियों को स्विस जैसे गाँवों पर भ्रमण के लिये ले जाना चाहिए। नेताओं के विदेश भ्रमण को सीमित करना चाहिए। National skill Development Corporation को चाहिए कि वह रोजगार के अवसर पैदा कराने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करे ताकि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा मिले। एग्रो फॉरेस्ट, पर्यटन, गायों की नस्ल सुधारने व कोल्ड स्टोर स्थापित करने की जरूरत है इजराइल की 'जुरान तकनीक' का इस्तेमाल इसके अन्तर्गत धुलाई से पैंकिटिंग तक स्वचलित मशीनों का इस्तेमाल होता है। रीठे के पेड़ रीठों से लदे रहते हैं जंगली जानवर भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है। जमीन पर पड़े रहते हैं बाजार की व्यवस्था नहीं है। उद्यम गांव में ही पैदा किये जाय, रोजगार मांगने नहीं वरन् पैदा करने की मानसिकता का विकास किया जाना चाहिए।

अध्ययन उद्‌देश्य

- गाँव के प्रति लोगों की बदली मनः स्थिति में परिवर्तन लाना।
- लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में सरकार पर गाँव का लोकनियंत्रण स्थापित कर Decision Making में भागीदार बनाना व उनके साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार करना ही शोध लेख का उद्‌देश्य है।
- प्रयोग के बाद गाँव की स्थिति में परिर्वतन हुआ है या नहीं तथा व्यवस्था से उदासीन है (या नौकरशाही पर निर्भर अन्त में समता, क्षमता, विभेदीकरण के आधार पर राज्य व्यवस्था में गाँव के सामान्वीकरण का आकलन।
-

अध्ययन पद्धति

प्रत्यक्ष रूप से इस गाँव से जुड़े रहने के कारण तथा चुनौती का अनुभव का भागीदार होने के कारण 'अनुभवात्मक' गाँव वालों की मनः स्थिति का पूरा अनुभव होने के कारण, मनोविश्लेषणात्मक व व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। (Sampling) न्यासदर्श के रूप में गाँव की अब की स्थिति पर सर्वे भी किया गया है। तटस्थता का निर्वाह करते हुए 'आधुनिक राजनीतिक निकास' उपागम का प्रयोग कर गाँव के संपूर्ण विकास संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है। अन्तर अनुशासनात्मक (Interdisciplinary) दृष्टिकोण का पूरा ख्याल रखा गया है। राजनीतिक विकास उपागम से गाँव की राजनीतिक समस्याओं का विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण व भविष्यवाणी करने में मद्द मिली है।

निष्कर्ष

पलायन भविष्य में रूकेगा संभावना नहीं लगती मनः स्थिति से तो यही लगता है कि जो लोग बचे हैं वे भी अपने बच्चों से इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। खन्न माफियाओं के माध्यम से शहर के नजदीक के पहाड़ी गाँवों की रोड किनारे की जमीनों पर कोठियां बनाने का काम काफी अधिक चल रहा है। परिणाम स्वरूप गांव की परम्परागत कृषि, दुग्ध उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन तथा घर के काम में मद्द न लेकर, शहर के नजदीक शिक्षा के लिए भेज रहे हैं ताकि भविष्य में वह भी उन्हीं की तरह सर पर लकड़ी, पानी, घास ही न ढोते रह जाये। शहर में एक सुविधाजनक मकान बना ले तथा ये परिवार भी अपने बच्चों के साथ चले जाये। पहाड़ के लोगों के पास शहर से ज्यादा दूध, फल, शब्जी है फिर भी कुपोषण के शिकार रहे सरकार आईटीआई तथा पॉलिटैक्निक एनआईसी कालेज तो पहाड़ों में कही पर खोलती है पर उद्योग नहीं परिणाम स्वरूप प्रशिक्षित बच्चे बाहर जाने को मजबूर होते हैं। 'सरकार' का गाँवों के प्रति कोई सारोकार नहीं है सही नीति नहीं होने के कारण पहाड़ों पर शराब व भूमाफिया का बोलवाला है रोजगार नहीं मिल रहा है नीतियां शहर के लिए बनती है। बड़ीक्राति व कुशल नेतृत्व की जरूरत है। पहाड़ का नेता चुनाव में पहाड़ में उम्मीदवार होता है जीतने के बाद मैदान में बड़ा Business man कारोबार का मालिक बन जाता है पहाड़ को मैदानी विकासीय दृष्टिकोण से न मापा जाय। आध्यात्मिक के स्रोत पहाड़ को बिकाऊ नहीं टिकाऊ बनाये रखने की जरूरत है।

References-

1. मुम्बई मौखिक 2016, पलायन पर विचार गोष्ठी
2. New Aspects of Political Development, ल्यूशियन पाई
3. समाचार पत्र पत्रिकाएं
4. Hindustan Times.com.india
5. Related Researches
6. पर्यावरणविद् श्री अनिल प्रकाश जोशी का हिमालयन यूनिटी मुवमेंट, गांव बचाओं आन्दोलन, अमर उजाला।
7. जुरान तकनीक, Food Processing and Post Harvesting Isereal. Aljazeera.com
8. राज्यपाल के0के0पॉल का पंतनगर विश्वविद्यालय के डा0 रतन सिंह आडिटोरियम में Skilling Uttrakhand विश्व प्रतिस्पर्धा विषयक, सेमिनार को सम्बोधन।
9. लेख – ' उत्तराखण्ड क्यों नही बना हिमांचल' द्वारा रामचन्द्र गुहा, अमर उजाला 22नवंम्बर 2015
10. लेख – 'गांव से पलायन रोकने की बनायेगें योजना' नीति नियोजन समूह के सदस्य सचिव की मुख्यमंत्री से बातचीत, अमर उजाला ब्यूरो।
11. लेख – ' प्रकृति सियायत नही करती ' थॉमस एल0 फ्रिडमेन।
12. सुरेश शर्मा – हिमालय विकास का मॉडल।
13. हैन्स हुबर – How Switzerland is governed.
14. Swiss Mountain villages , Review, Research works, Internet
15. The Codding - The Federal Govt. of Switzerland.